भारत सरकार

योजना मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4343

दिनांक 18.03.2026 को उत्तर देने के लिए

क्षेत्रीय असंतुलन

4343. **श्री वीरेन्द्र सिंह:**

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के पूर्वी और पिछड़े जिलों में अवसंरचना विकास के माध्यम से क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या विशेषकर उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में सड़क, रेल, संभार-तंत्र केंद्र (लॉजिस्टिक्स हब), औद्योगिक गलियारे या अन्य केन्द्रीय परियोजनाओं के अनुमोदन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (ग) भारत सरकार संतुलित क्षेत्रीय विकास को उच्च प्राथमिकता देती है और देश के पूर्वी और अपेक्षाकृत कम विकसित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के त्वरित विकास के माध्यम से क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का प्रयास कर रही है। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न क्षेत्रक कार्यक्रमों के माध्यम से बुनियादी ढांचे का विकास और कनेक्टिविटी में सुधार किया जा रहा है। प्रमुख पहलों में प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, भारतमाला परियोजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उच्च गति और अर्ध-उच्च गति रेलवे गलियारों का क्षमता संवर्धन और विकास, उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) स्कीम, सागरमाला, जल मार्ग विकास परियोजना, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, अमृत (अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन) और स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) शामिल हैं।

सरकार ने पूर्वी भारत को बुनियादी ढांचे के विकास, औद्योगीकरण और बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से एक प्रमुख विकास केंद्र में बदलने की पूर्वोदय के विजन वाली परिकल्पना प्रस्तुत की है। इस पहल के अंतर्गत, अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे के तहत औद्योगिक केंद्र, जिनमें गया का एक औद्योगिक केंद्र भी शामिल है, और पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे जैसी कनेक्टिविटी परियोजनाएं, साथ ही बक्सर में गंगा नदी पर एक अतिरिक्त दो-लेन पुल प्रस्तावित हैं। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत, पूर्वोदय राज्यों में चार औद्योगिक स्मार्ट शहरों - बिहार में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी) गया और आंध्र प्रदेश में कृष्णापटनम, ओरवाकल और कोप्पर्थी औद्योगिक क्षेत्र - को मंजूरी दी गई है और ये कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

साथ ही, उत्तर प्रदेश में 351 एकड़ में फैले एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी) प्रयागराज को भी मंजूरी दी गई है, जिसकी परियोजना लागत 658 करोड़ रुपये है। इससे लगभग 17,700 रोजगार सृजित होने और लगभग 1,600 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है।

केंद्रीय बजट 2026-27 में पूर्वी भारत के लिए पहलों पर विशेष बल दिया गया है। प्रमुख घोषणाओं में पूर्वी तट औद्योगिक गलियारे का विकास, पांच प्रमुख पर्यटन स्थलों का निर्माण, 4,000 ई-बसों की तैनाती और असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और अन्य उत्तरपूर्वी राज्यों में बौद्ध सर्किटों के विकास के लिए एक समर्पित योजना शामिल है। अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र में, डिब्रूगढ़ में कौशल विकास के लिए एक क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्र प्रस्तावित है, साथ ही कोलकाता और वाराणसी में अतिरिक्त प्रशिक्षण केंद्रों और अंतर्देशीय नौवहन और रसद को समर्थन देने के लिए वाराणसी और पटना में एक जलपोत मरम्मत प्रणाली का विकास भी प्रस्तावित है। इसके अलावा, ओडिशा में महानदी नदी प्रणाली पर राष्ट्रीय जलमार्ग-5 के लक्षित विकास की परिकल्पना की गई है ताकि तालचर और अंगुल जैसे खनिज समृद्ध क्षेत्रों को पारादीप और धामरा सहित औद्योगिक केंद्रों और बंदरगाहों से जोड़ा जा सके।

2018 में, भारत सरकार ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) की शुरुआत की, जो देश के सबसे सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े 112 जिलों को विकास और अवसरों के केंद्र में बदलने के लिए बनाई गई एक साहसिक पहल है। कार्यक्रम का मूल सिद्धांत सरल लेकिन गहरा है: "पिछड़ेपन" की सोच को "आकांक्षा" की ओर मोड़ना और डेटा-आधारित शासन, सहयोग और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से जिलों को उनकी छिपी क्षमता का एहसास कराने के लिए सशक्त बनाना।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश राज्य में संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा सड़कों, रेलवे और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाएं लागू की जा रही हैं, जिनमें चंदौली जिले

और उसके आसपास के क्षेत्र शामिल हैं, ताकि कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा सके और आर्थिक विकास को सुगम बनाया जा सके।

*****